IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) No, Sir. However, sharp increases in the prices of medicines which are outside the purview of price control under Drugs (Prices Control) Order, 1987 are monitored.

(c) Various aspects relating to price control are subject matter of the review of the Drug Policy 1986 which was discussed in the House on August 18, 19 and 23, 1993.

(d) No, Sir.

(e) and (f) Do not arise.

Sale of IDPL Units

871. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI GOVINDRAO RAMRAJ ADIK:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the news item published in the Financial Express of the 23rd November, 1993 under the Caption "Sale of IDPL units" imminent; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICAL AND FERTILIZERS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (b) Yes, Sir. No proposal for sale of the Madras and Muzaffarpur Units of Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited (IDPL) is under consideration at this stage.

किसानों को उर्वरकों पर राज सहायता

872. **श्री राम नरेश यादव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान उर्वरकों पर कितनी राशि की राजसहायता दी गई और वर्ष 1993-94 के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों की प्रतिटन उत्पादन-लागत क्या थी; और

(ग) किसानों को उर्वरकों के लिए प्रति टन कितनी राशि की राजसहायता प्रदान की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एडुआर्डो फलेरियो) : (क) किसानों को नियंत्रित उर्वरकों की बिक्री स्थानीय करों को छोड़ कर देश भर में सांविधिक रूप से अधिसूचित मूल्यों पर की जाती है । उर्वरक आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा अनुमानित उत्पादन के लागत की तुलना में बिक्री के जरिये अपेक्षाकृत कम प्राप्ति के लिए निर्माताओं को प्रतिपूर्ति दी जाती है । इसी तरह नियंत्रित आयातित उर्वरकों के मामले में किसानों से लिये जाने वाले बिक्री मूल्य और आयातों की लागत के मध्य अंतर को सरकार द्वारा वहन किया जाता है । गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भुगतान/वहन की गई उर्वरक आर्थिक सहायता निम्नानुसार थी :—

	(रु० करोड़)
1991-92 . .	4799.60
1992-93 . .	5799.99

इसके अलावा 1991-92 और 1992-93 के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा क्रमश: 405.00 करोड़ रु० के और 340 करोड़ रु० के बजट प्रावधान के साथ उर्वरकों पर कुछ विशेष आर्थिक